भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2396

21 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

धान की खरीद

2396. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार धान का पूरी तरह से एक-एक दाना खरीदने के वादे के बावजूद तेलंगाना के किसानों से धान की खरीद नहीं कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना से धान की कितनी खरीद की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा धान के लिए तेलंगाना के किसानों को प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कितनी राशि दी गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) तेलंगाना एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है जिसमें धान की खरीद राज्य सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से की जाती है और राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के बाद केवल अधिशेष चावल ही कमी वाले/उपभोक्ता राज्यों में संचलन के लिए केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सौंपा जाता है।

खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2022-23 के लिए, तेलंगाना राज्य के लिए 50 लाख टन चावल (74.62 लाख टन धान के बराबर) का खरीद अनुमान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार और एफसीआई के परामर्श से अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और कृषि फसल पैटर्न पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।

दिनांक 14.12.2022 तक, तेलंगाना में 74.62 लाख टन के अनुमान के मुकाबले, 9212.63 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का 44.72 लाख टन धान की खरीद की गई है।

...2/-

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदे गए धान की मात्रा और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार है

केएमएस	खरीदे गए धान (लाख टन में)	एमएसपी (रुपये प्रति क्विंटल में)	
		सामान्य	ग्रेड 'ए'
2017-18	54.00	1550	1590
2018-19	77.46	1750	1770
2019-20	111.26	1815	1835
2020-21	141.09	1868	1888
2021-22	119.05	1940	1960

*****